इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स का मासिक न्यूजलेटर प्रति माह 40/ रुपए
(आईएसओ 9001 : 2015 द्वारा प्रमाणित)

व्यावसायिक
उत्कृष्टता के
प्रति प्रतिबद्ध

आईआईबीएफ विजन

खंड : 11 अंक : 2 सितम्बर, 2018 पृष्ठों की संख्या 15

विजन : बैंकिंग और वित्त के क्षेत्र में सक्षम व्यावसायिक शिक्षित एवं विकसित करना।

मिशन : प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना।

इस अंक में

मुख्य घटनाएँ ----------2
विनियामकों के कथन ----------4
नयी नियुक्तियाँ----------6
उत्पाद एवं गठजोड़ ----------6
विदेशी मुद्रा ----------6
शब्दावली ----------7
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी ----------8
संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां ----------8
संस्थान समाचार ----------8
नयी पहलकदमी ---------- 12
बाजार की खबरें ----------13

इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना / समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों/ मीडिया में प्रकाशित हो चुकी/चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की/ किए जा रही / रहे हैं। उक्त सूचना/समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित/उल्लिखित घटनाएँ संबन्धित स्रोत द्वारा यथा-अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स समाचार मदों/घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी भी प्रकार से न तो उत्तरदाई है, न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।

मुख्य घटनाएँ

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने एकीकृत भुगतान अंतरापृष्ठ 2.0 की शुरुआत की

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) ने एकीकृत भुगतान अंतरापृष्ठ (UPI) सेवा के अपने उस उन्नत संस्करण - एकीकृत भुगतान अंतरापृष्ठ 2.0 को सक्रिय कर दिया है जो प्रयोक्ताओं को भावी लेनदेनों के लिए निधियों को अवरुद्ध करने तथा उसे पूर्व-प्राधिकृत करने में समर्थ बनाएगा । एकबारगी अधिदेश की सुविधा उपभोक्ताओं और व्यापारियों, दोनों को उपलब्ध होगी। उक्त कोटि-उन्नयन ग्राहकों को उनके ओवरड्राफ्ट खातों को एकीकृत भुगतान अंतरापृष्ठ से जोड़ने में समर्थ बनाएगा तथा वह तुरंत लेनदेन करने में समर्थ होगा। उक्त विशेषता उन प्रयोक्ताओं को लक्ष्यांकित करती है जिनके पास क्रेडिट कार्ड हो सकता है किन्तु जो डिजिटल भुगतान करते समय ऋण सुविधा का उपयोग करना पसंद करते हों।

इसके अतिरिक्त, व्यापारी भुगतान करते समय एकीकृत भुगतान अंतरापृष्ठ के प्रयोक्ता एक ऐसे डिजिटल बीजक तक पहुँचने में समर्थ होंगे जो व्यापारी के परिचय पत्र को देखने और उसका सत्यापन करने तथा उसके बाद सीवन-रहित (seemless) भुगतान करने में उनकी सहायता करेगा। हालांकि, यह कार्यात्मक विशेषता केवल ऐसे लेनदेनों के लिए ही कार्यक्षम होगी जिसमें व्यापारी का सत्यापन किया गया हो।

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर डा॰ ऊर्जित पटेल ने यह कहते हुए कि लागत चाहे जितनी भी क्यों न आए इस क्षेत्र में सभी तरह के प्रयास सरणिकृत किए जाने चाहिए पर्याप्त साइबर -सुरक्षा के महत्व को सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया है।

सेबी ने बाजार के मध्यवर्तियों/ बिचौलियों की उप-दलाल श्रेणी को समाप्त किया

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने बाजार के मध्यवर्तियों/बिचौलियों की उप-दलालॉ वाली उस श्रेणी को समाप्त कर दिया है जिसके लिए विनियामक के पास पंजीकरण की आवश्यकता हाती है। किसी भी व्यक्ति को नए उप-दलाल का पंजीकरण नहीं मंजूर किया जाएगा तथा पंजीकृत व्यक्तियों को एक प्राधिकृत व्यक्ति अथवा व्यापारिक सदस्य के रूप में कार्य करने हेतु वर्तमान वित्त वर्ष की समाप्ति तक का समय दिया जाएगा।

वर्तमान ढांचे के अधीन उप-दलालों के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के पास उसके शेयर दलाल और उप-दलाल मानदंडों के अधीन पंजीकरण कराना आवश्यक होता है, जबकि प्राधिकृत व्यक्तियों के लिए संबन्धित शेयर बाजार में पंजीकरण कराना आवश्यक होता है। हालांकि, उप-दलाल और प्राधिकृत व्यक्ति की परिचालनात्मक भूमिका में कोई अंतर नहीं होता।

सेबी ने ऋण प्रतिभूतियों के लिए सूचीकरण समय घटाए

ऋण प्रतिभूतियों को जारी किए जाने की प्रक्रिया को आसान एवं किफ़ायती बनाने के उद्देश्य से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने इसप्रकार की प्रतिभूतियों के सूचीकरण की समय-सीमा को वर्तमान में 12 दिनों से घटाकर छ: दिन कर दिया है। इसके अतिरिक्त, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने ऋण प्रतिभूतियों के सार्वजनिक निर्गम में आवेदन करते समय भुगतान करने वाले सभी निवेशकों के लिए

अवरुद्ध रकम द्वारा समर्थित आवेदन (ASBA) को अनिवार्य बना दिया है। अवरुद्ध रकम

द्वारा समर्थित आवेदन सुविधा से वसूलीकर्ता बैंकों के लिए भुगतान लिखतों का समाशोधन प्रारम्भ करने, बैंक अनुसूचियों के साथ आवेदन पत्रों को रजिस्ट्रार को अग्रेषित करने तथा तकनीकी अस्वीकृति जांच प्रारम्भ करने में लगने वाले समय में कमी आएगी। यह नया नियम 1 अक्तूबर, 2018 से ऋण प्रतिभूतियों के सभी सार्वजनिक निर्गमों पर लागू होगा।

सेबी ने प्रतिभूतियों को ई-बुक प्लेटफार्म पर जारी किए जाने की प्रक्रिया सरल की

प्रतिभूतियों को ई-बुक प्लेटफार्मों (EBP) पर जारी किए जाने की प्रक्रिया को आसान बनाए जाने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने निवेशकों को किसी निजी अभिनियोजन निर्गम में ऋण के आधार पर बहुविध/एकाधिक बोलियाँ (bids) लगाने की सुविधा प्रदान कर दी है तथा निक्षेपागारों (depositories) को सुसाधकों के रूप में कार्य करने की अनुमति भी दे दी है।

खुली बोली लगाने की वर्तमान प्रणाली के अलावा, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने जारीकर्ता द्वारा बोली लगाए जाने की विधि प्रकट किए जाने की शर्त पर ई-बुक प्लेटफार्मों पर सीमित (closed) बोली लगाए जाने की अनुमति भी दे दी है। हालांकि, सीमित बोली प्रणाली में ई-बुक प्लेटफार्मों पर बोलियों का यथार्थ समय प्रसारण नहीं होगा।

विनियामकों के कथन

असंगठित क्षेत्र से संबन्धित आंकड़े अपर्याप्त

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर डा॰ ऊर्जित पटेल ने मौद्रिक नीति निर्धारण, कराधान और दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान में दूरगामी सुधारों के लिए सरकार की सराहना

की है। उन्होंने कहा है कि "वास्तविक रूप से रूपांतरकारी सुधार प्रारम्भ करने में सरकार की दूरदर्शिता और असामान्य साहस का अव-आकलन नहीं किया जा सकता

और वैसा किया भी नहीं जाना चाहिए। ये सुधार आगामी दशकों में हमारे आर्थिक विकास को बेहतर रूप प्रदान करेंगे।"

गतिशील विश्व में किसी केंद्रीय बैंक द्वारा नयी सोच अपनाए जाने की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि अब ई -वाणिज्य, डिजिटल लेनदेनों तथा बड़े प्रति-वर्गीय (cross-sectional) आंकड़ों जैसे नए आयामों में निहित सूक्ष्म स्तर वाली मूल्य-निर्माण गतिशीलताओं को समझे जाने की आवश्यकता है। यह बैंकिंग, गैर-बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थीकरण, भुगतानों, मुद्रा प्रबंधन और उसके साथ ही वित्तीय समावेशन जैसे क्षेत्रों पर भी लागू होता है। अनुसंधान के अभाव में नीतिगत विकल्पों से कभी-कभी अवर–कोटि वाले इष्टतम परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। केंद्रीय बैंक परिवारों एवं फ़र्मों के व्यवहार को समझने के लिए सर्वेक्षणों और विश्लेषणों का सहारा लेता है।

डा॰ विरल आचार्य सार्वजनिक ऋण रजिस्ट्री के पक्ष में

सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की तुलना में ऋण अनुपात 55.7% होने के परिणामस्वरूप भारत में वित्तीय वित्तीय व्यापन में कमी को ध्यान में रखते हुये भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर डा॰ विरल आचार्य भारत में ऋण को लोकतान्त्रिक एवं औपचारिक बनाने हेतु एक सार्वजनिक ऋण रजिस्ट्री (PCR) की व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता महसूस करते हैं। उक्त सार्वजनिक ऋण रजिस्ट्री एक व्यापक डाटाबेस के साथ ऐसा एकल डाटा भंडार (रिपोजिटरी) हो सकती है जिसमें आकार संबंधी न्यूनतम सीमा के बिना देश के सभी ऋणदाताओं-उधारकर्ताओं के खातों का समावेश करते हुए सभी ऋण उत्पादों के मामले में ऋण के उद्गाम स्थल से लेकर उसकी समाप्ति तक की उनकी चुकौतियों, पुन: संरचना, चूक, समाधान जैसी सूचना के विवरण सहित ऋण संबंधी सूचनाओं का समावेश हो।

इससे उन्हें अन्य ऋणों के कार्य-निष्पादन को देख कर आस्ति की गुणवत्ता से संबन्धित समस्याओं के समय-पूर्व चेतावनी संकेतों को पहचानने और उसके बाद यह निर्णय लेने

मैं सहायता प्राप्त होगी कि कोई उधारकर्ता उनसे ऋण प्राप्त करने के योग्य है अथवा नहीं। ऋणदाता संस्थाओं के लिए उधारकर्ता से संबंधित सूचना में हिस्सेदारी करना कानूनन अनिवार्य होगा और सार्वजनिक ऋण रजिस्ट्री को सार्वजनिक ऋण रजिस्ट्री

अधिनियम द्वारा समर्थन प्रदान किया जाएगा। वर्तमान में इस प्रकार की सूचना किसी एकल क्षेत्र से नहीं उपलब्ध होती।

नयी नियुक्तियाँ

नाम	पदनाम/संगठन
श्री एस. गुरुमूर्ति	भारतीय रिजर्व बैंक के अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त
श्री सतीश मराठे	भारतीय रिजर्व बैंक के अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त

उत्पाद एवं गठजोड़

संगठन	जिसके साथ गठजोड़ हुआ वह संगठन	उद्देश्य
एक्जिम बैंक	ब्रिक्स बैंक	वितरित खाता-बही/ ब्लॉकचैन प्रौद्योगिकी में सहयोगी अनुसंधान करना।

विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियाँ

मद	24 अगस्त, 2018 के दिन बिलियन रुपए	24 अगस्त, 2018 के दिन मिलियन अमरीकी डालर
1. कुल प्रारक्षित निधियाँ	28,097.6	4,01,293.3
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	26,396.8	3,76,591.6
1.2 सोना	1,424.6	20,763.2

1.3 विशेष आहरण अधिकार	103.2	1, 471.6
1.4 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित निधि की स्थिति	173.0	2,466.9

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

सितम्बर, 2018 माह के लिए लागू अनिवासी विदेशी मुद्रा (बैंक) की न्यूनतम दरें

विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों की आधार दरें

मुद्रा	1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष	4 वर्ष	5 वर्ष
अमरीकी डालर	2.66400	2.82500	2.86600	2.87400	2.87500
जीबीपी	0.93400	1.1182	1.2256	1.3040	1.3680
यूरो	-0.22120	-0.142	0.013	0.145	0.28२
जापानी येन	0.05000	0.071	0.096	0.115	0.148
कनाडाई डालर	2.35000	2.429	2.494	2.532	2.555
आस्ट्रेलियाई डालर	1.97500	2.006	2.063	2.298	2.374
स्विस फ्रैंक	-0.61750	-0.531	-0.389	-0.259	-0.136
डैनिश क्रोन	-0.11020	-0.0067	0.1355	0.2825	0.4195
न्यूजीलैंड डालर	1.96300	1.988	2.081	2.196	2.322
स्वीडिश क्रोन	-0.29200	-0.100	0.100	0.275	0.458
सिंगापुर डालर	1.79000	1.943	2.038	2.108	2.168
हांगकांग डालर	2.39000	2.620	2.710	2.760	2.790
म्यामार	3.72000	3.720	3.760	3.810	3.850

स्रोत : www.fedai.org.in

शब्दावली

एकीकृत भुगतान अंतरापृष्ठ (UPI)

एकीकृत भुगतान अंतरापृष्ठ (UPI) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित एक संस्था/कंपनी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) द्वारा तैयार की गई एक त्वरित भुगतान प्रणाली है। एकीकृत भुगतान अंतरापृष्ठ तुरंत भुगतान प्रणाली की मूलभूत संरचना पर निर्मित है और वह किसी को दो पक्षों के खातों के बीच धन को तुरंत अंतरित करने में समर्थ बनाती

है। किसी ग्राहक के लिए निधियाँ विप्रेषित करने से पहले एकीकृत अंतरापृष्ठ के लिए पंजीकरण करना आवश्यक होता है, किन्तु निधियाँ अंतरित करने के लिए लाभार्थी के पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होती।

वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी

कुल आस्तियों की तुलना में अनिरुद्ध (liquid) आस्तियों का अनुपात

कुल आस्तियों में अनिरुद्ध (liquid) आस्तियों का उच्चतर स्तर बेहतर चलनिधि सुनिश्चित करेगा। इसलिए यह अनुपात जितना अधिक हो, उतना ही बेहतर है। अनिरुद्ध आस्तियों में बैंक में शेषराशियों, मांग एवं सूचना पर देय मुद्रा, एक माह के भीतर प्राप्य/देय अंतर-बैंक अभिनियोजनों, व्यापार के लिए धारित और तैयार बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध प्रतिभूतियों का समावेश हो सकता है।

संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां

अगस्त/सितंबर, 2018 माह के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

कार्यक्रम	तिथियाँ	स्थल
विधि अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	03 से 04 अक्तूबर, 2018	कोलकाता
प्रमाणित ऋण व्यावसायिक	17 से 19 सितंबर, 2018	प्रौद्योगिकी पर आधारित
	04 से 06 अक्तूबर, 2018	प्रौद्योगिकी पर आधारित
वित्तीय सेवाओं में जोखिम पर प्रमाणपत्र	17 से 19 सितंबर, 2018	मुंबई

संस्थान समाचार

परीक्षा शुल्क वसूल करने के नियमों में परिवर्तन

संस्थान ने 1 जुलाई, 2017 से सेवा कर के स्थान पर माल एवं सेवा कर (GST) प्रणाली अपना ली है। एसोसिएट, डिप्लोमा और मिश्रित पाठ्यक्रमों के लिए परीक्षा शुल्क वसूल करने के पूर्ववर्ती नियम में यह निर्धारण था कि अभ्यर्थियों को दो प्रयासों के लिए परीक्षा शुल्क का भुगतान एक साथ करना होगा। माल एवं सेवा शुल्क प्रावधानों का पालन करने

तथा कर भुगतान प्रबंधन को सरल बनाने के लिए शुल्क वसूल करने से संबन्धित नियम को पुनर्विन्यस्त किया गया है। अब संस्थान प्रत्येक प्रयास के लिए अभ्यर्थियों से परीक्षा शुल्क अलग-अलग वसूल करेगा। अतएव, अभ्यर्थियों को प्रत्येक प्रयास के लिए अलग-अलग पंजीकरण करवाना होगा।

"बैंकिंग: आगामी दशक में पदार्पण" पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन

संस्थान ने 2018 में बैंकिंग उद्योग की 90 वर्षों की समर्पित सेवा पूरी कर ली है और इस अवसर का स्मरणोत्सव मनाने के लिए हम 25 सितंबर, 2018 को होटल ट्राइडेंट, बांद्रा-कुर्ला काम्प्लेक्स, मुंबई में "बैंकिंग: आगामी दशक में पदार्पण" पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं।

बैंकों में क्षमता निर्माण

भारतीय रिजर्व बैंक ने 11 अगस्त, 2016 की अपनी अधिसूचना के द्वारा यह अनिवार्य कर दिया है कि प्रत्येक बैंक के पास परिचालन के प्रमुख क्षेत्रों में उपयुक्त योग्यता/प्रमाणन सहित कर्मचारियों को परिनियोजित करने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक नीति होनी चाहिए। प्रारम्भिक तौर पर उन्होंने निम्नलिखित क्षेत्र अभिज्ञात किया है :

- खजाना प्रबंधन : व्यापारी, मिड आफिस परिचालन।
- जोखिम प्रबंधन : ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, परिचालन जोखिम, उद्यम-व्यापी जोखिम, सूचना सुरक्षा, चलनिधि जोखिम।
- लेखांकन – वित्तीय परिणाम तैयार करना, लेखा-परीक्षा कार्य।
- ऋण प्रबंधन : ऋण मूल्यांकन, श्रेणी-निर्धारण, निगरानी, ऋण संचालन।

कालांतर में भारतीय रिजर्व बैंक के निदेश पर भारतीय बैंक संघ ने उपयुक्त संस्थाओं एवं ऐसे पाठ्यक्रमों की पहचान के लिए एक विशेषज्ञ दल का गठन किया था, जो आवश्यक प्रमाणन प्रदान कर सकें। इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैंस उनमें से एक तथा एकमात्र ऐसी संस्था है जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अभिज्ञात चार में से तीन क्षेत्रों में उक्त प्रमाणन प्रदान

करती है।

इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय बैंक संघ को संबोधित तथा प्रति इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैंस को पृष्ठांकित दिनांक 31 मई, 2017 के अपने पत्र के तहत यह कहा है कि <u>भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ के सहयोग से इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स द्वारा उपलब्ध कराया जाने वाला विदेशी मुद्रा में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम ऐसे</u> सभी बैंक कर्मचारियों, जो खजाना परिचालन सहित विदेशी मुद्रा परिचालन के क्षेत्र में कार्यरत है या कार्य करने के इच्छुक हैं, के लिए एक अनिवार्य प्रमाणन होगा।

संस्थान द्वारा खजाना परिचालन, जोखिम प्रबंधन और ऋण प्रबंधन के क्षेत्र में उपलब्ध कराये जाने वाले पाठ्यक्रम आनलाइन परीक्षा के साथ प्रकृति की दृष्टि से मिश्रित हैं जिसके बाद उनमें
ऐसे अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है जिन्होंने आनलाइन परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर ली है। परीक्षा हेतु पंजीकरण और अधिक विवरण के लिए वेबसाइट www.iibf.org.in.देखें।

चार्टर्ड बैंकर इंस्टीट्यूट, एडिनबर्ग, यू. के. के साथ पारस्परिक मान्यता करार

संस्थान को चार्टर्ड बैंकर इंस्टीट्यूट, एडिनबर्ग, यू. के. के साथ पारस्परिक मान्यता करार हस्ताक्षरित होने की घोषणा करते हुये प्रसन्नता होती है। इस करार के अधीन भारत स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकर्स के प्रमाणित सहयोगी (CAIIB) अपनी अर्हताओं को चार्टर्ड बैंकर इंस्टीट्यूट द्वारा मान्यता दिलवाएँगे तथा वे संस्थान के व्यावसायिकता, आचारशास्त्र एवं विनियम माड्यूल का अध्ययन करके और परावर्तक दायित्व को सफलतापूर्वक पूरा करके चार्टर्ड बैंकर बनने में समर्थ होंगे।

प्रौद्योगिकी पर आधारित कक्षा में समाधान

संस्थान ने प्रौद्योगिकी पर आधारित कक्षा वाली विधि के माध्यम से प्रशिक्षण संचालित करने हेतु एक साफ्टवेयर अभिगृहीत किया है। यह साफ्टवेयर गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी लाये बिना संस्थान को प्रशिक्षार्थियों की काफी बड़ी संख्या तक प्रशिक्षण सामग्री

प्रसारित करने में समर्थ बनाएगा। वित्तीय सेवाओं में जोखिम में प्रौद्योगिकी पर आधारित प्रशिक्षण भी आरंभ कर दिया गया है। अधिक विवरण के लिए हमारी वेबसाइट www.iibf.org.in देखें।

परीक्षा के लिए छद्म जांच सुविधा

संस्थान अपने प्रमुख पाठ्यक्रमों यथा जेएआईआईबी और सीएआईआईबी के अलावा अपने तीन विशिष्टीकृत पाठ्यक्रमों नामत: प्रमाणित खजाना व्यावसायिक, प्रमाणित ऋण व्यावसायिक तथा वित्तीय सेवाओं में जोखिम के लिए छद्म जक्ष्च की सुविधा प्रदान कर रहा है। अब छद्म जक्ष्च में किसी भी बैंक का कर्मचारी शामिल हो सकता है।

मुंबई और कोलकाता स्थित संस्थान के स्वयं अपने परीक्षा केन्द्रों में परीक्षाएँ

इसके पूर्व संस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME), ग्राहक सेवा और धन-शोधन निवारण/आतंकवाद के वित्तीयन का मुक़ाबला नामक अपने तीन पाठ्यक्रमों के लिए प्रत्येक महीने के दूसरे और चौथे शनिवारों को मुंबई एवं कोलकाता स्थित स्वयं अपने परीक्षा केन्द्रों में परीक्षाएँ आयोजित करता था। अब ऊपर वर्णित परीक्षाएँ प्रत्येक महीने के 1ले और 3रे शनिवारों को आयोजित की जाएंगी। अभ्यर्थीगण अपनी पसंद की परीक्षा की तिथि एवं केंद्र का चयन कर सकते हैं। पंजीकरण पहले आए, पहले पाये के आधार पर होगा। उपर्युक्त पाठ्यक्रमों की परीक्षा का कार्यक्रम हमारी वेबसाइट www.iibf.org.in.**पर** उपलब्ध है।

आगामी अंकों के लिए बैंक क्वेस्ट की विषय-वस्तुएं

बैंक क्वेस्ट के आगामी अंकों के लिए निर्धारित विषय-वस्तुयें निम्नानुसार हैं :
बैंकिंग : आगामी दशक में पदार्पण – जुलाई –सितंबर, 2018

जोखिम प्रबंधन और सूक्ष्म अनुसंधान आलेख 2018 : अक्तूबर – दिसंबर, 2018
पारस्परिक निधियाँ : जनवरी –मार्च, 2019
बैंकों में आचारशास्त्र और कारपोरेट अभिशासन : अप्रैल - जून, 2019
बैंकिंग में उभरते प्रौद्योगिकीय परिवर्तन : जुलाई - सितंबर, 2019

12

परीक्षाओं के लिए दिशानिर्देशों /महत्वपूर्ण घटनाओं की निर्धारित तिथि

संस्थान में इस बात की जांच करने के उद्देश्य से कि अभ्यर्थी अपने –आपको वर्तमान घटनाओं से अवगत रखते हैं या नहीं प्रत्येक परीक्षा में कुछ प्रश्न हाल की घटनाओं/ विनियामक/कों द्वारा जारी दिशानिर्देशों के बारे में पूछे जाने की परंपरा है। हालांकि, घटनाओं/दिशानिर्देशों में प्रश्नपत्र तैयार किए जाने की तिथि से और वास्तविक परीक्षा तिथि के बीच की अवधि में कुछ परिवर्तन हो सकते हैं। इन मुद्दों का प्रभावी रीति से समाधान करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि :

(i) संस्थान द्वारा फरवरी, 2017 से जुलाई, 2017 तक की अवधि के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में प्रश्नपत्रों में समावेश के लिए विनियामक/कों द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में 31 दिसंबर, 2016 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।

(ii) संस्थान द्वारा अगस्त, 2017 से जनवरी, 2018 तक की अवधि के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में प्रश्नपत्रों में समावेश के लिए विनियामक/कों द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों
और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में 30 जून, 2017 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।

नई पहलकदमी

सदस्यों से अनुरोध है कि वे संस्थान के पास मौजूद उनके ई-मेल पते अद्यतन करा लें तथा वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के जरिये प्राप्त करने हेतु अपनी सहमति भेज दे।

आईआईबीएफ विजन के स्वामित्व और अन्य विवरणों से संबन्धित वर्णन

इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स का जर्नल

1. प्रकाशन स्थल	**: मुंबई**
2. प्रकाशन की आवधिकता	**: मासिक**
3. प्रकाशक का नाम	**: डा. जिबेन्दु नारायण मिश्र**
राष्ट्रीयता	**: भारतीय**

पता	**: इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स कोहिनूर सिटी, कामर्शियल- II, टावर** 1**, किरोल रोड, कुर्ला** (प)**, मुंबई**- 400 070
4. संपाद्क का नाम	**: डा. जिबेन्दु नारायण मिश्र**
राष्ट्रीयता	**: भारतीय**
पता	**: इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स कोहिनूर सिटी, कामर्शियल- II, टावर** 1**, किरोल रोड, कुर्ला** (प)**, मुंबई**- 400 07**0**
5 प्रिन्टिंग प्रेस का नाम	**: आनलुकर प्रेस, 16 सासून डाक, कोलाबा, मुंबई**- 400 005
6. स्वामियों के नाम एवं पता	**: इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स कोहिनूर सिटी, कामर्शियल- II, टावर** 1**, किरोल रोड, कुर्ला** (प)**, मुंबई**- 400 07**0**

मैं, डा. जे. एन. मिश्र, एतदद्वारा यह घोषणा करता हूं कि ऊपर दिये गए विवरण मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य हैं।

31-03-2017 **डा. जे. एन. मिश्र**

प्रकाशक के हस्ताक्षर

समाचार पंजीयक के पास आरएनआई संख्या 692**2**8/1998 **के अधीन पंजीकृत**

बाजार की ख़बरें

भारित औसत मांग दरें

स्रोत : भारतीय समाशोधन निगम न्यूजलेटर, अगस्त, 2018

भारतीय रिजर्व बैंक की संदर्भ दर

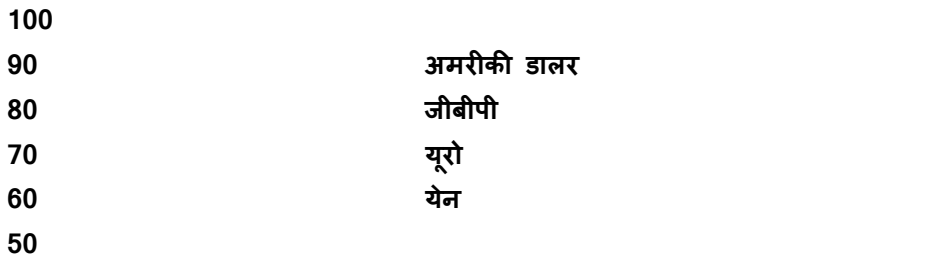

मार्च, 2018, अप्रैल, 2018, मई, 2018, जून, 2018, जुलाई, 2018, अगस्त, 2018
स्रोत : फाइनैन्सियल बेंचमार्क बोर्ड आफ इंडिया लिमिटेड (FBIL)

खाद्येतर ऋण वृद्धि %

फरवरी, 2018, मार्च, 2018, अप्रैल, 2018, मई, 2018, जून, 2018, जुलाई, 2018
स्रोत : मंथली रिव्यू आफ इकानामी, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, अगस्त, 2018

बंबई शेयर बाजार सूचकांक

40000.00
38000.00
36000.00
34000.00

15

32000.00
30000
28000
26000

मार्च, 2018, अप्रैल, 2018, मई, 2018, जून, 2018, जुलाई, 2018, अगस्त, 2018
स्रोत : बंबई शेयर बाजार (B S E)

समग्र जमा वृद्धि %

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
फरवरी, 2018, मार्च, 2018, अप्रैल, 2018, मई, 2018, जुलाई, 2018अगस्त, 2018
स्रोत : मंथली रिव्यू आफ इकानामी, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, अगस्त, 2018

डा. जे. एन. मिश्र द्वारा मुद्रित, डा. जे. एन. मिश्र द्वारा इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स की ओर से प्रकाशित तथा आनलुकर प्रेस, 16 सासुन डाक, कोलाबा, मुंबई- 400 018 में मुद्रित एवं इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स, कोहिनूर सिटी, कामर्शियल-II, टावर-1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम),,मुंबई – 400 070 से प्रकाशित।
संपादक : डा. जे. एन. मिश्र

इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स
कोहिनूर सिटी, कामर्शियल-II**, टावर**-1**, 2री मंजिल,**
किरोल रोड, कुर्ला (**पश्चिम**)**, ,मुंबई** – **400 070**
टेलीफोन : 91-22-2503 9604/ 9607 **फैक्स** : **91-22-2503 7332**
तार : INSTIEXAM **ई-मेल** : admin@iibf.org.in.
वेबसाइट : www.iibf.org.in.

आईआईबीएफ विजन सितंबर, 2018